सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

जल है तो कल है

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-6 • 04 APRIL TO 10 APRIL 2025 • VOLUME 36 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता...

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

CONFUSED ABOUT CAREER!

Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?

Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?

Should I consider Computer or Mechanical Engineering?

What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?

Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?

Do I have the aptitude for Architecture and Designing?

Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.

*T&C apply

सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर

खनन नीति में संशोधनों को मंजूरी

● कीमतें घटाने और रेत एवं बजरी की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय ● तीर्थ यात्रा स्कीम को मिला 100 करोड़ का बजट, अब 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी ले सकेंगे स्कीम का लाभ

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में अवैध खनन को रोकने और रेत व बजरी की कीमतों को और कम करने का रास्ता साफ कर दिया। इस संबंध में निर्णय यहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 'पंजाब राज्य माइनर मिनरल नीति' में संशोधन करने के लिए सहमति दे दी है। इसका उद्देश्य बाजार में कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाना, अवैध खनन और भ्रष्टाचार को कम करना, राज्य का राजस्व बढ़ाना और खनन क्षेत्र में संभावित एकाधिकार को खत्म करना है। यह संशोधन क्रशर माइनिंग साइट्स (सी.आर.एम.एस.) से संबंधित है, जिसके तहत क्रशर मालिक, जिनके पास बजरी वाली जमीन है, अब खनन लीज प्राप्त कर सकेंगे। इस कदम से अन्य राज्यों से खनन सामग्री की अवैध परिवहन पर रोक लगने की संभावना है। इससे बाजार में कुचली हुई रेत और बजरी की उपलब्धता बढ़ेगी, जो राज्य में विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक है। इसी तरह लैंडऑनर माइनिंग साइट्स (एल.एम.एस.) के तहत रेत वाली जमीनों के मालिकों को सुविधा होगी और वे खनन लीज के लिए आवेदन कर सकेंगे तथा खनन सामग्री को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में बेच सकेंगे।

पहले जमीन मालिकों की सहमति न होने के कारण कई खनन स्थल कार्यशील नहीं थे, क्योंकि जमीन मालिक अपनी जमीन से किसी अज्ञात व्यक्ति को खनन की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं होते थे। एल.एम.एस. की शुरुआत से कार्यशील खनन स्थलों की संख्या बढ़ेगी, जिससे बाजार आपूर्ति बढ़ने के साथ-साथ राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। यह कदम खनन क्षेत्र में एकाधिकार को खत्म करेगा।

डिप्टी कमिश्नरों को सरकारी और पंचायती जमीनों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी.) जारी करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि वे इन जमीनों के संरक्षक होते हैं। यह बदलाव प्रक्रिया को सुचारु बनाएगा और सरकारी जमीनों पर खनन स्थलों के संचालन को तेज करेगा। रेत पर रॉयल्टी बढ़ाकर 1.75 रुपए प्रति क्यूबिक फीट कर दी गई है, जिसकी पिट-हेड कीमत 7 रुपए प्रति क्यूबिक फीट है। बजरी/आर.बी.एम. पर रॉयल्टी बढ़ाकर 3.15 रुपए प्रति क्यूबिक फीट कर दी गई है, जिसकी पिट-हेड कीमत 9 रुपए प्रति क्यूबिक फीट है। मंत्रिमंडल ने दोहराया कि पंजाब सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये संशोधन न केवल खनन के हितधारकों की जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि पूरे राज्य में खनन गतिविधियों के कानूनी और पारदर्शी संचालन के लिए एक उपयुक्त ढांचा भी स्थापित करेंगे। इस नीति का लक्ष्य पर्यावरण और नियामक मानकों को बनाए रखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम' को हरी झंडी : मंत्रिमंडल ने राज्य में 'स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम' (विद्यार्थियों को प्रेरणा देने का प्रयास) लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारी राज्य भर के ग्रामीण स्कूलों को गोद लेंगे और विद्यार्थियों को अपने जीवन में ऊंचाइयां छूने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। यह पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले राज्य के 80 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' में शुरू होगा और प्रत्येक अधिकारी को पांच साल के लिए स्कूल आवंटित किया जाएगा, चाहे इस दौरान उनकी तैनाती कहीं भी हो। इस कदम से आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों का विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ सार्थक संवाद होगा, जिससे शिक्षा का माहौल और अधिक अनुकूल होगा। ये अधिकारी जहाँ विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरणा देंगे, वहीं शिक्षकों के कौशल को निखारने के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे। ये अधिकारी इन स्कूलों के विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये अधिकारी बॉस के रूप में नहीं, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणा देंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्य स्वैच्छिक होगा और इसमें रुचि रखने वाले अधिकारियों को अपनी पहले से निर्धारित ड्यूटी के साथ-साथ इस कर्तव्य को निभाना होगा।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के प्रस्तावों को मंजूरी

इसी तरह 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। यात्रा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, जिसमें वातानुकूलित यात्रा, आरामदायक आवास और भोजन-पान की व्यवस्था आदि सुविधाएं शामिल होंगी। यात्रा को यादगार बनाने के लिए सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को स्मृति-चिन्ह के रूप में उपहार भी दिया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि 50 वर्ष और इससे अधिक उम्र के सभी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना हर जाति, धर्म, आय और क्षेत्र के लोगों के लिए है। पंजाब के सभी शहरों और गांवों के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यात्रा का उद्देश्य राज्य की समृद्ध आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मूर्त रूप देना है और इसमें सभी प्रमुख धार्मिक स्थानों की यात्राएं शामिल होंगी। प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा के दौरान सत्संग और कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियां भी होंगी। यात्रा पूरी होने के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और यदि जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जाएगा। तीर्थ यात्रा पर जाने वालों के लिए पंजीकरण अप्रैल के आखिरी सप्ताह से शुरू होगा और यात्रा मई में शुरू होगी।

राज्यसभा में नड्डा ने गिनाई वक्फ विधेयक की खूबियां

नई दिल्ली. राज्यसभा के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि यह देश के हित में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष वक्फ विधेयक को बुलडोज करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि सदन भी इसका समर्थन करेगा। मुझे उम्मीद है कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण, दक्षता और विकास का समर्थन होगा। इस विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में सुधार और उचित प्रबंधन लाना है। इस पर बहुत चर्चा हुई है। नड्डा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए इस वक्फ विधेयक को ध्वस्त करने के लिए शोर मचाया जा रहा है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के

राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं इस शोर को रोकता हूँ और इस नैरेटिव का विरोध करता हूँ। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में कहा जाता है कि 'जब आपके पास तर्क होते हैं, तो आप तर्कपूर्ण होते हैं और उसी के अनुसार बोलते हैं, और जब आपके पास तर्क नहीं होते, तो आप अपनी आवाज उठाते हैं और सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं।' मैंने देखा कि बहस पटरी से उतर गई और भटक गई। मैंने कल लोकसभा में भी यही देखा।

जेपी नड्डा ने दावा किया कि वक्फ संशोधन बिल देश के हित में है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से जवाबदेही बनाने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यधारा में मुस्लिम बहनों को लाने से कांग्रेस ने रोका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी कोशिश सिर्फ नियमों के दायरे में लाना है।

अमेरिका द्वारा लगाए टैरिफ के प्रभाव का आकलन कर रहा भारत : वित्त राज्य मंत्री

नई दिल्ली. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अमेरिका की शुल्क बढ़ोतरी और देश पर इसके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। यहां पीएफआरडीए द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत पर इसके प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका आकलन जारी है। अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का मानना है कि अमेरिकी वस्तुओं पर भारत उच्च आयात शुल्क वसूलता है, ऐसे में अब देश के व्यापार घाटे को कम करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। इस कदम से अमेरिका को भारत के निर्यात पर असर पड़ने के आसार हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जिन्हें हमसे अधिक शुल्क का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लगभग 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है।

हेरोइन सहित गिरफ्तारी के एक दिन बाद महिला कांस्टेबल को नौकरी से किया बर्खास्त

चंडीगढ़ (जालंध ब्रीज). नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए शुरू किए गए 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम के अंतर्गत त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर (बैज नंबर: 621/एम एन एस) को नशे से संबंधित मामले में शामिल होने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी आज यहां पुलिस मुख्यालय के इंस्पेक्टर जनरल (आईजीपी) डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने दी। यह कार्रवाई बठिंडा पुलिस की टीमों द्वारा आरोपी अमनदीप कौर को उसकी काले रंग की महिंद्रा थार, जिसे वह चला रही थी से 17.71 ग्राम हेरोइन बरामद कर गिरफ्तार करने के एक दिन बाद ही की गई। पुलिस टीमों ने उसकी थार गाड़ी, जिसका पंजीकरण नंबर पीबी 05 एक्यू 7720 है, को भी जब्त कर लिया है। दोषी महिला कांस्टेबल अस्थायी रूप से पुलिस लाइन बठिंडा में तैनात थी। आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को बर्खास्त करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

चब्बेवाल ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की मुलाकात

नई दिल्ली/होशियारपुर (जालंधर ब्रीज). सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बिलाचौर-होशियारपुर-दसूहा सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग

घोषित करने और इसे और चौड़ा करने की मांग रखी, जिससे इस क्षेत्र में सुगम यातायात के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। केंद्रीय मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात के दौरान लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने उन्हें अवगत कराया कि बलाचौर-होशियारपुर-दसूहा सड़क पंजाब के कई जिलों को जोड़ने के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ती है।

मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री से की मुलाकात

बैंकाक (जालंधर ब्रीज). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने थाईलैंड की अपनी आधिकारिक यात्रा पर बैंकॉक में प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा से मुलाकात की। गवर्नमेंट हाउस पहुंचने पर मोदी की अगुवाई प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने की और उनका औपचारिक स्वागत किया। यह उन दोनों की दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले दोनों ने अक्टूबर 2024 में वियनतियाने में आसियान से संबंधित शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की। उन्होंने राजनीतिक आदान-प्रदान, रक्षा और सुरक्षा भागीदारी, रणनीतिक जुड़ाव, व्यापार और निवेश और दोनों देशों के लोगों को बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। ऐसा करते हुए दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्टार्ट-अप, नवाचार, डिजिटल, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन सहयोग बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर घोटालों सहित अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किए।

गर्मजोशी से स्वागत

बैंकॉक के डॉन मुआंग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के आगमन पर सिख समुदाय के लोगों ने भांगड़ा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया।

वक़्फ़ संशोधन : मुस्लिम समुदाय के कल्याण हेतु पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन के लिए आह्वान

कहा- वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी ने अक्षमताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया

जालंध ब्रीज. भारत के धार्मिक और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के सामाजिक और बेहद विविध ताने-बाने में, वक़्फ़ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन यह अब तक पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाई है। इस्लामी आध्यात्मिक परंपरा में गहराई से समाई हुई यह वैधानिक इकाई भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि, अपनी समृद्ध विरासत और विशाल भूमि संपत्तियों के बावजूद, वक़्फ़ अक्षमताओं, कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी की वजह से पिछड़ गया है।

यह वास्तव में विरोधाभासी है कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी भूमि स्वामित्व वाली इकाई के रूप में वक़्फ़ एक ऐसे समुदाय की देखरेख करता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के मुद्दों से जूझ रहा है। सदियों पहले स्थापित वक़्फ़ का मूल उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के लिए स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय और अन्य परोपकारी संस्थानों की स्थापना और देखरेख करना था। यह चिंता का विषय है कि इतना विशाल संसाधन आधार होने के बावजूद इन्हें समुदाय के कल्याण के लिए प्रभावी रूप से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। प्रस्तावित उम्मीद वक़्फ़ विधेयक संशोधन का उद्देश्य वक़्फ़ को परेशान करने वाले कुछ पुराने मुद्दों को संबोधित करना है। ये सुधार अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में

-हाजी सैयद सलमान चिश्ती, अध्यक्ष चिश्ती फ़ाउंडेशन

व्यापक रूप से यह सहमति बन चुकी है कि वक़्फ़ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है। कई मुतवल्ली (संरक्षक), जो जिम्मेदारी निभाने योग्य नहीं हैं, इन संपत्तियों के कुप्रबंधन के जिम्मेदार रहे हैं। वक़्फ़ बोर्ड की अक्षमताओं के कारण इन संपत्तियों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो पाया है।

वक़्फ़ की वर्तमान स्थिति भारत में मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों का प्रतिबिंब है। वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी ने अक्षमताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

मौजूदा वक़्फ़ व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या वक़्फ़ के स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए अप्रचलित किराया नीति है। इनमें से कई संपत्तियां दशकों पहले तय की गई दरों पर किराए पर दी गई हैं, अक्सर 1950 के दशक तक। न केवल ये किराए आज के बाजार दर से बेहद कम हैं, बल्कि यह मामूली किराया भी नियमित रूप से नहीं वसूला जाता है। यह स्थिति वक़्फ़ संपत्तियों की अवैध बिक्री और बरबादी के आरोपों से और भी जटिल हो गई है, जिसने संभावित राजस्व को काफी हद तक नष्ट कर दिया है और जिसका उपयोग सामुदायिक कल्याण के लिए किया जा सकता था। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण जयपुर शहर का सबसे केंद्रीय और प्रसिद्ध शॉपिंग स्ट्रीट है, जिसे एमआई रोड के रूप में जाना जाता है और जो सांगानेरी गेट से गवर्नमेंट हॉस्टल तक जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि एमआई का मतलब मिर्जा इस्माइल रोड है। जयपुर में एमआई रोड पर स्थित कुछ संपत्तियां सामुदायिक और धार्मिक कार्यों के लिए वक़्फ़ बोर्ड को दान कर दी गई हैं। बोर्ड इन संपत्तियों को किराए पर दे सकता है, लेकिन किसी को बेच नहीं सकता। एमआई रोड पर 100 वर्ग फीट से लेकर 400 वर्ग फीट तक की कई ऐसी व्यावसायिक संपत्तियां हैं, जिनका किराया 300 रुपये प्रति माह है, किराया नीति अद्यतन होने पर इनका किराया करीब 25,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर राज्य में ऐसी हजारों संपत्तियां हैं, जिनका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

सच्चर समिति की 2006 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि वक़्फ़ अपनी संपत्तियों से सालाना 12,000 करोड़ रुपये की आय का सृजन कर सकता है। हालांकि, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षणों से अब पता चलता है कि वक़्फ़ संपत्तियों की वास्तविक संख्या 8.72 लाख से अधिक है। आज, मुद्रास्फीति और संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, संभावित आय सालाना 20,000 करोड़ रुपये तक हो सकती है। फिर भी, वास्तविक राजस्व 200 करोड़ रुपये ही है - जो पेशेवर और पारदर्शी प्रबंधन के साथ प्राप्त की जा सकने वाली आय का एक अंश है।

सामुदायिक कल्याण में राजस्व सृजन और निवेश की संभावना बहुत अधिक है। यदि कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाए, तो वक़्फ़ संपत्तियां विश्व स्तरीय संस्थानों - स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, और बहुत कुछ - की स्थापना के लिए धन दे सकती हैं, जो न केवल भारतीय मुस्लिम समुदाय, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज की सेवा कर सकती हैं। यहीं पर हमें, भारतीय मुसलमानों के रूप में, "कल्याण" की अपनी समझ को व्यापक बनाना चाहिए। कल्याण का मतलब मुफ्त, खस्ताहाल संस्थान नहीं है, जो खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके बजाय, हमें ऐसे संस्थानों के निर्माण की आकांक्षा करनी चाहिए, जो आत्म-निर्भर हों, समावेशी हों तथा ऐसे उच्च मानकों वाले हों कि वे सभी के लिए आकांक्षापूर्ण बन जाएं।

रिश्वत लेने के आरोप में सब-इंस्पेक्टर और उसका साथी गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने एक सब-इंस्पेक्टर और उसके साथी प्राइवेट ऑपरेटर को 20,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान केंद्रीय जेल फिरोजपुर में तैनात पुलिस चौकी इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर सरवन सिंह और उसके साथी प्रदीप सिंह (प्राइवेट ऑपरेटर) के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कुलदीप सिंह, निवासी मथेरे गांव, जिला फिरोजपुर की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है। इस संबंध में दोनों आरोपियों के खिलाफ पी.सी. (संशोधन) मुताबिक संधोधित एक्ट 2018 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत फिरोजपुर के वी.बी. रेंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

रिश्ते में नई जान भर देगा यह सफर, जानें क्यों जरूरी है कपल टूरिज्म

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का सबसे मुफीद तरीका होता है, साथ में सफर करना। माना कि जिंदगी में बच्चे के आने के बाद उन्हें छोड़कर कहीं घूमने जाने का विकल्प हम भारतीयों के गले नहीं उतरता। पर, यकीन मानिए आप दोनों के रिश्ते की बेहतरी के लिए नियमित अंतराल पर सिर्फ आप दोनों का कहीं घूमने जाना जरूरी है। साथ घूमना रिश्ते की बेहतरी के लिए क्यों है जरूरी, आइए जानें:

रुटीन से छुट्टी : प्यार का रंग नए-नए अनुभवों के आधार पर गाढ़ा होता है। शादीशुदा जिंदगी अमूमन एक तय ढर्रे पर चलती है, जिसमें हम सब हर दिन अमूमन एक जैसी भूमिका ही निभा रहे होते हैं। एक जैसी रुटीन, एक जैसी जिम्मेदारियों को पूरा करते-करते कब जिंदगी पर नीरसता हावी होने लगती है, पता ही नहीं चलता। इस नीरसता को खत्म करने और जिंदगी में नई ऊर्जा भरने में हमसफर के साथ नियमित अंतराल पर छोटे-छोटे ट्रिप्स आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। घर से दूर किसी नई जगह पर जब हम अपने साथी के साथ घूम रहे होते हैं, तो इस क्रम में एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है, आपसी विश्वास बढ़ता है और साथ ही भावनात्मक रिश्ता भी मजबूत होता है।

साथ बनाएं योजना : हमसफर के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बनाने का साइड इफेक्ट कोई आपसे

TRAVELLING **आपसी रिश्ते की मासूमियत, रोमांच और खुशी के लिए सिर्फ साथी के साथ घूमने जाना भी जरूरी है। विशेषज्ञ इसे कपल ट्रिरिज्म का नाम देते हैं। आपसी रिश्ते की बेहतरी के लिए साथी के साथ सफर पर जाना क्यों है जरूरी...**

पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? मेरी मानिए तो योजना बनाने के दौर का सबसे नकारात्मक पहलू है- अपेक्षाओं में अंतर। जहां एक साथी नई जगह के चप्पे-चप्पे को देख लेना चाहता है, हर पल को तसवीरों में कैद करना चाहता है, वहीं दूसरा एक-दो जगह घूमने के बाद आराम से बिस्तर में लेटना चाहता है। अपेक्षाओं का यह अंतर इतने पैसे खर्च करने के बावजूद आपकी छुट्टियों को बर्बाद कर सकता है। इस परेशानी से बचने का एक ही तरीका है- साथ मिलकर छुट्टियों की पूरी योजना बनाना। आपकी छुट्टियां कितनी मजेदार और संतोषजनक होगी, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि यात्रा की योजना कितनी बेहतर बनी है।

सफर की सरदर्दी में प्यार : पहले से तय योजनाओं के मुताबिक सफर में हर काम हो जाए तो फिर वह सफर कैसा! ट्रेन और फ्लाइट का देर हो जाना, सामान छूट जाना, भूख लगी हो और कोई सलीके का रेस्टोरेंट न मिलना, अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाना...इन सबका तो सफर

से अभिन्न रिश्ता है। सफर के दौरान इन सब उठा-पटक का आप दोनों एक जोड़े के रूप में कैसे सामना करती हैं, वह आपके रिश्ते के बारे में काफी कुछ बता सकता है। ये चुनौतियां एक जोड़े के रूप में समस्याओं का सामना करना और उससे उबरना आप दोनों को सिखाएंगी। सफल जोड़े सफर के दौरान सामने कोई मुसीबत आने पर साथ मिलकर उसका हल तलाशते हैं न कि एक-दूसरे की गलतियां निकालते हैं। सफल जोड़े मुसीबत आने पर एक-दूसरे पर चीखने-चिल्लाने की जगह साथ मिलकर उसका समाधान तलाशते हैं।

गप्प कीजिए खूब : रोज के रुटीन, ऑफिस का ईमेल, घर के काम, बच्चों का होमवर्क...इन सबसे परे हमसफर के साथ असली बातचीत का मौका अगर चाहिए तो सिर्फ जीवनसाथी के साथ घूमने जाने की योजना नियमित अंतराल पर बनाइए। दैनिक जिम्मेदारियों से इतर साथी के साथ वक्त बिताना, उनसे बातें करना... आपको साथी के साथ जुड़ने का ऐसा मौका देगा जो घर पर जिम्मेदारियों के बोझ तले आप दोनों को ही नहीं मिल पाता। इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए और दिल खोलकर एक-दूसरे से बातचीत कीजिए।

साथी के बारे में जानने का मौका : साथी के साथ घूमने-फिरने के फायदों में से एक है, उनके बारे में कुछ नया जानने का अवसर। घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बीच शादी के कुछ साल बाद ऐसा महसूस होने लगता है कि पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। पर, साथ सफर करने से पूर्वाग्रह से मुक्ति पाने का मौका मिलता है। नई जगह की खूबसूरती को निहारते, नई संस्कृति को अपनाते हुए और वहां नई-नई गतिविधियों को आजमाते हुए अपने जीवनसाथी को देखकर उनके बारे में फिर से कई नई बातें पता चलती हैं। साथ सफर करने से संभव है कि आपको अपने जीवनसाथी से दोबारा से प्यार हो जाए।

अध्ययनों की जुबानी : जर्नल ऑफ ट्रैवल रिसर्च में प्रकाशित आलेख के मुताबिक जो जोड़े साथ में सफर करते हैं, उनका आपसी संवाद बेहतर होता है। एक हजार शादीशुदा अमेरिकियों पर किए गए सर्वे में पाया गया कि जो लोग अपनी शादी से संतुष्ट थे, उनमें से 84 प्रतिशत जोड़े नियमित रूप से साथ में घूमने जाते हैं। सर्वे में पाया गया 90 प्रतिशत जोड़े जो हनीमून के बाद तीन से चार बार साथ घूमने जा चुके थे, वे अपने रिश्ते से ज्यादा संतुष्ट थे। जो लोग रिश्ते से संतुष्ट नहीं थे, उनमें से 78 प्रतिशत साथ में कहीं घूमने कभी-कभार ही जाते थे। साथ में सफर करने की मुख्य वजह अधिकांश जोड़ों के लिए एक-दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताना है।

ध्यान की तरह है हमारे लिए घूमना : ये हैं सवि और विदित। ये दोनों ट्रैवल इंफ्लूएंसर हैं। हमसफर हैं और एक साथ 107 से भी ज्यादा देशों और सैंकड़ों शहरों की यात्रा कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पर ब्रूज्ड पासपोर्ट के नाम से इनका अकाउंट है। अपने इस अनूठे सफर के बारे में बात करते हुए दोनों बताते हैं, 'हम दोनों पिछले 17 सालों से साथ सफर कर रहे हैं और हम पूरे दावे से यह बात कह सकते हैं कि साथ में घूमने-फिरने से हम कई तरीके से एक-दूसरे के नजदीक आए हैं। हम दोनों ही इस कहावत को सच मानते हैं कि जो जोड़े साथ घूमते हैं, वे साथ रहते हैं। नई जगह घूमने, नए लोगों से मिलने और नए नजारों को देखकर हम दोनों हर बार कुछ नया सीखते हैं।' सवि कहती हैं कि विदित के साथ नए-नए अनुभव साझा करते हुए हर बार घूमने-फिरने का मेरा अनुभव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लगातार साथ में घूमने से हमारा रिश्ता कई गुना मजबूत हुआ है। विदित कहते हैं, 'घूमना हम दोनों के लिए ध्यान करने की तरह है। सफर के दौरान हर बार हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कई ऐसी चीजें सीखते हैं, जो नौकरी करते हुए शायद हम कभी भी सीख नहीं पाते।'

BEAUTY CARE

ग्लोइंग स्किन पाने के लिए चेहरे पर लगाएं अंडा, इन 3 तरीकों से बनाएं फेस पैक

बालों के साथ-साथ अंडा स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। इसे स्किन पर कई तरह से लगाया जा सकता है। यहां हम 3 तरीकों से अंडे का फेस पैक बनाने का तरीका बता रहे हैं। जानिए-

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

अंडे का इस्तेमाल अधिकतर महिलाएं बालों के लिए करती हैं। इसके कंडीशनिंग गुण बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अंडा आपकी स्किन के लिए भी उतना ही अच्छा है? दरअसल, अंडे में बहुत सारे हेल्दी फैट होते हैं जो स्किन की चमक को बनाए रखने में मदद करते हैं। अंडे की सफेदी भी फाइन लाइन्स और झुर्रियों को रोकने में बहुत कारगर होती है। अंडे की सफेदी से आप फेस पैक तैयार कर सकते हैं। यहां देखिए अंडे से फेस पैक बनाने का तरीका।

1) सेंसेटिव स्किन के लिए अंडे का फेस मास्क

इस फेस पैक को बनाने के लिए

आपको चाहिए

1 अंडे का सफेद भाग
1 चम्मच दही
1 चम्मच शहद
1 चम्मच खीरे का रस

कैसे बनाएं और लगाएं

इस फेस पैक को बनाने के लिए सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर चेहरे को धो लें और मॉइस्चराइजर लगाएं। अच्छे रिजल्ट के लिए इसे हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें।

2) एक्ने वाली स्किन के लिए अंडे का फेस मास्क

इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए

1 अंडे का सफेद भाग
आधे नींबू का रस

कैसे बनाएं और लगाएं

इस फेस पैक को बनाने के लिए दोनों चीजों को एक साथ मिलाएं और फेंटें। फिर इसे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाएं। 15 मिनट तक लगा रहने दें फिर गुनगुने पानी से धोएं और मॉइस्चराइजर लगाएं। इसे हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करें।

3) ब्लैकहेड्स से छुटकारे के लिए अंडे का फेस मास्क

इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए-

1 अंडे का सफेद भाग
एक पेपर टॉवल या टिशू

कैसे बनाएं और लगाएं

इसे बनाने के लिए अंडे के सफेद भाग को तब तक फेंटें जब तक कि उसमें झाग न आ जाए। फिर इसे ब्रश से अपने चेहरे पर लगाएं। अब पेपर टॉवल को अपने चेहरे पर रखें। अंडे के सफेद भाग के मिक्स की एक और लेयर लगाएं। इसे 10 मिनट तक लगा रहने दें। जब सूख जाए तो धीरे-धीरे टॉवल को हटाएं। फिर अपना चेहरा धोएं और मॉइस्चराइजर लगाएं। अच्छे रिजल्ट के लिए इसे हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

दाल फ्राई और दाल तड़का में होता है फर्क, क्या आप जानते हैं?

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

रेस्तरां के मेन्यू में खाने पीने की कई आइटम होती हैं। लेकिन एक आइटम जिसे देखकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वह है दाल फ्राई और दाल तड़का। अधिकतर लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही डिश हैं। लगे भी क्यों न आखिर दोनों में एक जैसी दालों का इस्तेमाल जो होता है। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। क्योंकि ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। आइए, जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है।

दाल फ्राई और दाल तड़के में क्या है अंतर

दाल तड़का और दाल फ्राई को लेकर लोग अक्सर यही सोचते हैं की दोनों एक जैसी ही होती हैं। आमतौर पर दोनों तरह की दालों को तूअर और मूंग या मसूर दाल से बनाया जाता है। दोनों में मसाले भी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन बनाने की प्रक्रिया में कुछ खास अंतर होता है जिससे दोनों के स्वाद में फर्क होता है। इन दोनों तरह की दालों के बीच खास अंतर तड़के का है। दाल तड़का में दाल पकने के बाद तड़का डाला जाता है, जबकि दाल फ्राई में दाल पकाने के समय पर ही मसाले और प्याज डाले जाते हैं।

अलग है दोनों को बनाने की प्रक्रिया

दाल फ्राई के लिए टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों और मसालों को बहुत सारे मक्खन, घी या तेल में पकाया जाता है और फिर पकी हुई दाल को उस मिक्स में डालकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है। जिससे दाल में की बनावट और स्वाद जबरदस्त हो जाता है। वहीं दाल तड़का के लिए लहसुन, सूखी मिर्च और पिसे हुए मसालों के साथ सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इसे भी गरम घी या तेल में हल्का तला जाता है और फिर पकी हुई दाल के ऊपर डाला जाता है। इससे ऊपर मसालों की एक अलग परत बन जाती है जिसे सर्व करने पर मिक्स किया जाता है।

बच्चों को कैसे सिखाएं बातचीत का तरीका, जरूरी है सोशल स्किल की नॉलेज

PARENTING

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

बच्चों के अंदर गुड कम्यूनिकेशन स्किल डेवलप करना जरूरी होता है। जिससे कि उनके अंदर सोशल स्किल बनें। खुद के मन में चल रही बातों को एक्सप्रेस करने के साथ ही फ्रेंड्स बनाना और लोगों से बातचीत करने की नॉलेज देना बचपन से ही जरूरी है। जिससे कि बड़े होकर वो किसी भी अनजान इंसान से बात करने में खुद को अनकंफर्टेबल ना फील करें और ना ही कॉन्फिडेंस की कमी हो। जान लें कैसे बच्चों के अंदर बातचीत करने की स्किल डेवलप करने में पैरेंट्स हेल्प करें।

बच्चों से अलग-अलग टॉपिक पर बात करें

बच्चों की कम्यूनिकेशन स्किल सुधारनी है तो सबसे पहले पैरेंट्स को बच्चों से बात करनी होगी। अलग-अलग टॉपिक पर बच्चों के साथ बात करें। फेवरेट बुक्स से लेकर हॉबीज और यहां तक कि देश-दुनिया के टॉपिक पर भी बच्चों के साथ बात करें। इससे बच्चों के अंदर बोलने और बातचीत करने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है।

बच्चों से पूछें 'आज दिनभर क्या हुआ'

बच्चों से बातचीत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका उनके स्कूल और हॉबी क्लासेज के बारे में बातचीत करना है। उनसे पूछें कि आज दिनभर क्या हुआ। उन्होंने क्या सीखा, क्या मस्ती की। ऐसा पूछने से बच्चे खुद की बातों को अच्छी तरह से बोल पाते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं और मन की फीलिंग्स को भी बता पाते हैं।

रोज प्रैक्टिस है जरुरी

किसी भी दूसरी स्किल की तरह बातचीत के लिए भी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बच्चे से हर दिन बात करें और बहुत थोड़े शब्दों में जवाब ना दें। इससे बच्चे ज्यादा शब्दों के जरिए बोलना सीख पाएंगे।

बच्चों के साथ बुक पढ़ें

बच्चे के अंदर कम्यूनिकेशन स्किल डेवलप हो इसके लिए साथ में बुक्स पढ़ें। जिससे उसकी वर्ड पावर बढ़े और वो उन शब्दों को यूज करना सीख पाए। इससे बच्चों

महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के लिए खतरनाक है बेली फैट, तेजी से होता है कैंसर

HEALTH **महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कमर और पेट पर चढ़ा फैट खतरनाक है। इससे मोटापा और कई तरह के कैंसर का रिस्क महिलाओं की तुलना में कहीं ज्यादा होता है...**

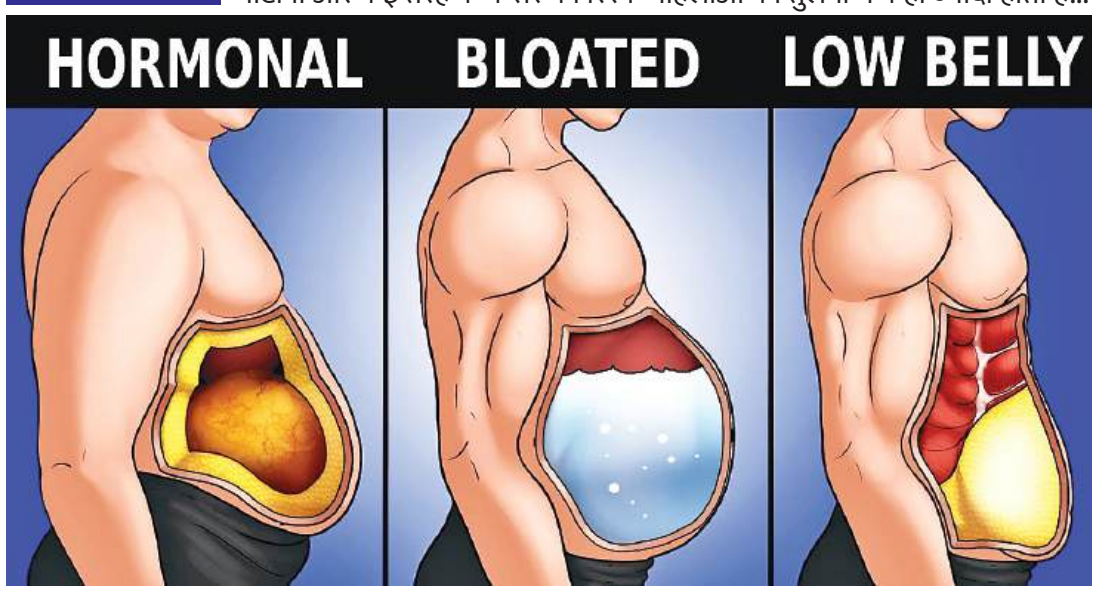

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

मोटापा वैसे तो कई सारी बीमारियों की जड़ है। लेकिन इसकी वजह से कैंसर का भी रिस्क रहता है। खासतौर पर शरीर के कुछ खास हिस्सों पर जमा बॉडी फैट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। अगर किसी पुरुष के तोंद निकली है यानी बेली फैट है तो ये सेहत के लिए खतरनाक है। नई रिसर्च में पता चला है कि कमर का घेरा अगर ज्यादा है तो कैंसर का रिस्क भी उतना ज्यादा है। लेकिन ये खतरा महिलाओं को नहीं केवल पुरुषों को है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के जर्नल में पब्लिश नई रिसर्च को मई में स्पेन के मलागा में मोटापे पर होने वाले यूरोपीय कांग्रेस में प्रेजेंट किया जाएगा। जिसमे कैंसर के प्रीडिक्शन के लिए बीएमआई से ज्यादा सटीक बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन को माना गया है।

स्वीडिश लोगों पर किया गया रिसर्च

3,40,000 स्वीडिश लोगों के डेटा जिनकी एवरेज उम्र 51 साल के करीब है, को एनालाइज किया गया। जिसमे उनके 1981 से लेकर 2019 के बीच बॉडी मास इंडेक्स और कमर के घेरे को देखा गया। इन आंकड़ों को कंपेयर करके पाया गया कि 14 सालों में 18,185 मोटापे से जुड़े कैंसर मरीजों में डायग्नोस हुए।

कमर के इंच बढ़ने से बढ़ जाता है कैंसर का खतरा

पुरुषों में कमर के घेरे का साइज बढ़ने के साथ ही कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। कमर के 11 सेमी तक बढ़ने से ये रिस्क 25 फीसदी ज्यादा हो जाता है। वहीं स्टडी में पाया गया कि महिलाओं में 12 सेमी तक कमर बढ़ने और बीएमआई बढने पर कैंसर का रिस्क केवल 13 प्रतिशत ही है।

मोटापे की वजह से होता है इन कैंसर का रिस्क

मोटापा होने पर इसोफेगस यानी आहार नली का कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, कोलन कैंसर, लीवर कैंसर, गालब्लैडर, पैनक्रियाज, ब्रेस्ट (पोस्टमेनोपॉजल), एंडोमेट्रियम, ओवरी, रेनल सेल सर्किनोमा, मेनिन्जियोमा, थायराइड और मल्टीपल मायलोमा जैसे कैंसर का खतरा रहता है।

बीएमआई से ज्यादा एक्यूरेट है कमर का साइज

कैंसर का पता करने के लिए बीएमआई से ज्यादा सटीक कमर का साइज है। बॉडी मास इंडेक्स से भले ही बॉडी साइज का पता चलता हो लेकिन ये शरीर में फैट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी नहीं देता। जबकि कमर के घेरे की मदद से ज्यादा करीब से पेट के मोटापे का पता चलता है। विसरल फैट, जो ज्यादातर पेट के आसपास जमा होता है, वो मेटाबॉलिक ज्यादा एक्टिव होता है और हेल्थ पर असर डालता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंफ्लेमेशन, ब्लड में आसामान्य फैट का लेवल ये सारे विसरल फैट से इफेक्टेड होते हैं। इसलिए एक ही बीएमआई के होने के बावजूद फैट के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के अलग होने पर कैंसर का रिस्क भी अलग-अलग होता है।

महिलाओं की तुलना में पुरुषों को क्यों है ज्यादा खतरा

सामान्य तौर पर देखा जाए तो महिलाओं के ज्यादातर पेरिफेरल फैट होता है जो बाजू और पैर पर चढ़ता है, वहीं विसरल फैट पेट पर जमा होता है, जो आमतौर पर पुरुषों में देखा जाता है। ज्यादातर पुरुषों के फैट इकट्ठा होने की जगह पेट होती है, जिससे तोंद निकल आती है।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

विश्व को नया आकार देने वाले भू-राजनीतिक रुझानों से निपटना

जालंधर ब्रीज

अमिताभ कांत
(लेखक भारत के जी20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।)

ट्रम्प प्रशासन अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ और 'अमेरिका को फिर से महान बनाने' की नीतियों पर दोगुना जोर दे रहा है। ट्रम्प प्रशासन अतीत के गठबंधनों को फिर से परिभाषित और पुनर्लेखन करने का काम भी कर रहा है जिसकी गूंज यूरोप और एशिया में उनके सहयोगियों द्वारा महसूस की जा रही है। इन कदमों का उद्देश्य व्यापार संतुलन में सुधार और सार्वजनिक व्यय को कम करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अमेरिका ने पेरिस समझौते व विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से खुद को अलग कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से भी वह पहले ही अलग हो चुका है। ये कदम वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवस्था में एक शून्य पैदा कर रहे हैं। यह शून्य लंबे समय तक नहीं रहेगा-इसे प्रतिस्पर्धी शक्तियों द्वारा भरा जाएगा। अमेरिका सबसे शक्तिशाली बना हुआ है और हम एक बार फिर एक बहुध्रुवीय दुनिया का उदय देख रहे हैं। विखंडित वैश्वीकरण, तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई, ऊर्जा की भू-राजनीति और ढहता वैश्विक शासन विश्व को नया आकार देने वाले प्रमुख भू-राजनीतिक रुझान हैं जिनसे भारत को निपटना होगा।

वैश्वीकरण का विखंडन : जैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में हमने जो वैश्वीकरण का युग देखा था, वह समाप्त होने वाला है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से, हमने वैश्वीकरण का विखंडन देखा है। व्यापार युद्धों ने इस विखंडन को और तेज़ कर दिया है। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारी व्यवधान पैदा किया और इसके फलस्वरूप देशों और व्यवसायों को वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने के लिए प्रेरित किया। ट्रम्प प्रशासन द्वारा फिर से टैरिफ़ लगाने के साथ, व्यापार युद्धों का दूसरा युग हमारे सामने है। चाहे पारस्परिक हो या सभी टैरिफ़, व्यापार युद्ध विश्व व्यापार को बहुत ज़्यादा बाधित करेंगे। व्यापार युद्ध अब सिर्फ़ बिक्री की वस्तुओं के बारे में नहीं रह गए हैं। वे प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और औद्योगिक नीति जैसे कारकों को प्रभावित करते हैं। देश ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उद्योगों में संरक्षणवाद और क्षमताओं का निर्माण करने का सहारा ले रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अधर में लटके होने के साथ, देश द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार समझौतों की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फ्रेंड-शोरिंग का उदय और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने का लक्ष्य भारत के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। हम सही नीतियों, रणनीतिक द्विपक्षीय व्यापार सौदों और व्यापार सुगमता पर ध्यान केंद्रित करके विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर सकते हैं।

प्रौद्योगिकी-वैश्विक शक्ति के लिए युद्ध का मैदान : प्रथम औद्योगिक क्रांति से लेकर चौथी तक वैश्विक शक्ति गतिशीलता को आकार देने में प्रौद्योगिकी प्रमुख प्रेरक शक्ति रही है। आज के युग में, सेमीकंडेक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां प्रमुख प्रेरक शक्ति हैं। राष्ट्र तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए चिप निर्माण में अरबों रुपए डाल रहे हैं। एआई में देशों और कंपनियों से समान रूप से बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। साथ ही, साइबर युद्ध और एआई द्वारा उत्पन्न जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साइबर युद्ध पूरे ऊर्जा ग्रिड को बाधित कर सकता है या भुगतान और बैंकिंग प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। एआई द्वारा संचालित भ्रामक सूचना चुनावों को बाधित कर सकते हैं और सामाजिक कलह को जन्म दे सकते हैं। एआई को दुनिया भर के समुदायों द्वारा आकार दिया जाना चाहिए, स्वामित्व में लिया जाना चाहिए और तैनात किया जाना चाहिए। हमें कुशलता से नवाचार करना चाहिए, कम से कम में अधिक करना चाहिए, ओपन सोर्स और सरल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना चाहिए और बहुभाषी और मल्टीमॉडल मॉडल बनाना चाहिए। वैश्विक समुदाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रौद्योगिकी, नुकसान को सीमित करते हुए समावेशी हो। भारत मॉडल, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग विभाजन को बढ़ाने के बजाय उसे पाटने के लिए किया जाता है, दुनिया के लिए एक आदर्श हो सकता है।

ऊर्जा की भू-राजनीति और ऊर्जा परिवर्तन : स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव शक्ति गतिशीलता को फिर से परिभाषित कर रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्वों) से समृद्ध राष्ट्र या इन महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को नियंत्रित करने वाले देश अधिक प्रभावशाली बन रहे हैं। आज, लगभग 70-80 प्रतिशत दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) निष्कर्षण और प्रसंस्करण चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दुनिया के 80 प्रतिशत सौर सेल चीन द्वारा उत्पादित किए जाते हैं और इसी तरह लगभग 70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी भी चीन द्वारा उत्पादित की जाती हैं। चीन पहले से ही तकनीकी अपनाने के मामले में आगे है, ट्रम्प प्रशासन के तहत अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हो गया है और इसके बजाय वह जीवाश्म ईंधन विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा जोखिम पैदा करता है। विकसित राष्ट्र पहले ही वैश्विक कार्बन बजट का 80 प्रतिशत हिस्सा खर्च कर चुके हैं और जी7 देशों से कोयले का चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन अब 2030 के बजाय 2035 तक होगा। इसके अलावा, विकसित राष्ट्र विकासशील देशों को जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी में विफल हो रहे हैं। इससे विकासशील देशों के लिए अपनी विकास महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत कम जगह बचती है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर हमारी दौड़ को वैश्विक गठबंधनों के नए रूपों की आवश्यकता है। देशों को अगली पीढ़ी के सौर पैनल, इलेक्ट्रोलाइज़र और वैकल्पिक सेल केमिस्ट्री (एसीसी) बैटरी जैसी तकनीक पर सहयोग करना चाहिए। भारत को निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अपने घरेलू इकोसिस्टम का निर्माण जारी रखना चाहिए। हमें प्रसंस्करण और शोधन के लिए क्षमताओं का विकास करते हुए महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापार साझेदारी भी सुरक्षित करनी चाहिए।

बढ़ते वैश्विक संघर्ष के बीच ढहता वैश्विक शासन : ऐसे समय में जब वैश्विक सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है, हमारे पास जो संरचनाएं हैं, वे विफल हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। वैश्विक तापमान पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस के सीमा को पार कर चुका है। ग्लोबल साउथ, अपने प्रतिनिधित्व और अपनी प्राथमिकताओं दोनों के मामले में हाशिये पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गतिरोध बना हुआ है, विश्व व्यापार संगठन में विवाद समाधान तंत्र का अभाव है और कॉप29 बहुत जरूरी जलवायु वित्त पोषण प्रदान करने में विफल रहा है। यूक्रेन से लेकर गाजा और सूडान तक, दुनिया भर में संघर्ष बढ़ रहा है। जैसा कि पीएम मोदी ने बार-बार कहा है, जलवायु परिवर्तन, महामारी और वित्तीय अस्थिरता की आज की चुनौतियां राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं देखती हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हम पुरानी संस्थाओं के साथ 21वीं सदी की चुनौतियों से नहीं लड़ सकते। एक नए वैश्विक शासन ढांचे की आवश्यकता है जो ग्लोबल साउथ को अपने केंद्र में रखे और यह स्वीकार करे कि दुनिया अब कुछ चुनिंदा शक्तियों का क्षेत्र नहीं है। यह क्षण भारत के लिए एक वैकल्पिक वैश्विक आर्थिक मॉडल को आकार देने और अधिक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की वकालत करने का एक अवसर है।

आने वाला दशक वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देगा। भारत उभर रहा है और वैश्विक मंच पर एक व्यावहारिक नेता के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है। हम ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने ला रहे हैं जबकि वैश्विक संघर्ष पर एक समझौतावादी रुख अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री का हालिया बयान कि हमें मतभेद के बजाय संवाद पर जोर देना चाहिए, ने वैश्विक स्तर पर एक गूंज पैदा की है। भारत का कूटनीतिक संतुलन इस युग की एक परिभाषित विशेषता बन रहा है।

दृष्टिकोण से विजय तक : भारत किस प्रकार टीबी के विरुद्ध अपनी लड़ाई को नया स्वरूप दे रहा है

जालंधर ब्रीज

जगत प्रकाश नड्डा
(लेखक भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं।)

इस विश्व टीबी दिवस पर, मैं इस बात पर बहुत गर्व के साथ विचार करता हूँ कि भारत टीबी के खिलाफ़ लड़ाई में किस तरह से अपनी रणनीति को फिर से लिख रहा है। हाल ही में संपन्न 100-दिवसीय सघन टीबी-मुक्त भारत अभियान ने न केवल नवाचार की शक्ति का प्रदर्शन किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि समुदायों को संगठित करना कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण को बदलने जितना ही महत्वपूर्ण है। यह अभियान 7 दिसंबर 2024 को टीबी के मामलों का पता लगाने में तेज़ी लाने, मृत्यु दर को कम करने और नए मामलों को रोकने के उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था।

100-दिवसीय सघन टीबी-मुक्त भारत अभियान ने टीबी का जल्द पता लगाने के लिए अत्याधुनिक रणनीतियाँ पेश कीं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि बिना लक्षण वाले लोगों की भी पहचान हो - जिनका अन्यथा निदान नहीं हो पाता - और उनका इलाज किया गया। पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों को सीधे उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के पास ले जाया गया, जिनमें मधुमेह, धूम्रपान करने वाले, शराब पीने वाले, एचआईवी से पीड़ित लोग, बुजुर्ग और टीबी रोगियों के घरेलू संपर्क मैं रहने वाले शामिल थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित एक्स-रे ने संदिग्ध टीबी मामलों को तुरंत चिह्नित किया, और स्वर्ण-मानक न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट (NAAT) का उपयोग करके पुष्टि की गई। इन प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि संक्रामक मामलों की पहचान की गई और उनका जल्दी से इलाज किया गया, जिससे संक्रमण पर लगाम लगी और लोगों की जान बचाई गई।

यह अभियान देश के कोने-कोने तक पहुँचा, जिसमें वे लोग जिनमें टीबी का खतरा अधिक है के 2.97 करोड़ लोगों की जाँच की गई। इस गहन प्रयास के कारण 7.19 लाख टीबी रोगियों की पहचान की गई, जिनमें से 2.85 लाख मामले बिना लक्षण वाले थे और इस अभिनव दृष्टिकोण के बिना अन्यथा छूट जाते, जिससे टीबी संक्रमण की श्रृंखला टूट गई। यह सिर्फ़ एक मील का पत्थर नहीं है - यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

टीबी मुक्त भारत अभियान: एक जन आंदोलन : लेकिन असली गेम-चेंजर सिर्फ़ तकनीक नहीं थी - यह समुदायों की अभूतपूर्व लामबंदी थी। टीबी उन्मूलन अब जनभागीदारी द्वारा संचालित एक जन आंदोलन है। पूरे भारत में 13.46 लाख से ज़्यादा निक्षय शिविर आयोजित किए गए, जहाँ माननीय सांसदों, विधायकों और पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों सहित 30,000 से ज़्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का समर्थन किया। कॉरपोरेट पार्टनर और आम नागरिक इस अभियान में शामिल हुए, जिससे यह विचार मज़बूत हुआ कि टीबी उन्मूलन सिर्फ़ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि एक सामूहिक मिशन है। और इस मिशन में जनभागीदारी का उदाहरण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में देखा गया, जहाँ 22 संबंधित मंत्रालयों में टीबी जागरूकता, पोषण किट वितरण, टीबी मुक्त भारत के लिए शपथ लेने जैसी 35,000 से ज़्यादा गतिविधियाँ की गईं। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, व्यापार संघों, व्यावसायिक संघों, स्वैच्छिक संगठनों के साथ 21,000 से अधिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं और 78,000 शैक्षणिक संस्थानों में 7.7 लाख से अधिक छात्रों ने टीबी जागरूकता और संवेदीकरण गतिविधियों में भाग लिया। जेलों, खदानों, चाय बागानों, निर्माण स्थलों और कार्य स्थलों जैसे सामूहिक स्थानों पर 4.17 लाख से अधिक संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग और परीक्षण किया गया। अभियान अवधि के दौरान त्यौहारों पर 21,000 से अधिक टीबी जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें धर्म आधारित नेताओं और सामुदायिक प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण, जिसने जन-भागीदारी की आधारशिला रखी, न केवल पोषण के लिए बल्कि मनोसामाजिक और व्यावसायिक समर्थन के लिए रोगियों को गोद लेने के लिए व्यापक सामाजिक समर्थन जुटाया। टीबी रोगियों के लिए सहायता अब अस्पतालों तक सीमित नहीं है - यह घरों, गांवों और कार्यस्थलों पर भी हो रही है। नि:क्षय मित्र पहल के माध्यम से, व्यक्ति और संगठन टीबी से पीड़ित परिवारों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें हज़ारों पोषण किट पहले ही वितरित की जा चुकी हैं। सिर्फ़ 100 दिनों में, 1,05,181 नए नि:क्षय मित्रों को नामांकित किया गया। पोषण और टीबी से उबरने के बीच महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए, सरकार ने नि:क्षय पोषण योजना के तहत वित्तीय सहायता को ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी टीबी रोगी इस लड़ाई को अकेले न लड़े।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी टीबी रोगियों के लिए विभेदित टीबी देखभाल कार्यक्रम के तहत अनुकूलित और व्यक्तिगत उपचार प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी टीबी रोगी का वजन कम पाया जाता है (बीएमआई < 18.5 किग्रा/ मीटर2), तो उनके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उनके लिए अनुकूलित पोषण और उपचार योजना तैयार करेंगे और उपचार के दौरान हर महीने उनकी प्रगति की निगरानी करेंगे।

इस अभियान की गति ने यह भी दर्शाया है कि कैसे समाज और सरकार का समग्र दृष्टिकोण परिवर्तनकारी बदलाव ला सकता है। टीबी जागरूकता और सेवाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत करने के लिए 22 मंत्रालयों ने मिलकर काम किया। टीबी जागरूकता झांकियां गोवा कार्निवल परेड का मुख्य आकर्षण बन गईं। देश भर के स्कूलों में, टीबी जागरूकता संदेशों को सुबह की सभाओं में शामिल किया गया। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हजारों आगंतुकों को मुफ्त टीबी जांच की पेशकश करने के लिए अपने क्लस्टर कार्यालयों के नेटवर्क का लाभ उठाया। इन विविध प्रयासों ने कलंक को तोड़ दिया, गलत सूचनाओं को सही किया और टीबी उन्मूलन को सार्वजनिक चेतना के केंद्र में ला दिया। 100 दिवसीय अभियान अभी शुरुआत है। भारत इन प्रयासों को पूरे देश में बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर नागरिक - चाहे वे कहीं भी रहते हों - को आधुनिक निदान, गुणवत्तापूर्ण उपचार और अटूट सामुदायिक समर्थन तक पहुँच प्राप्त हो। जिस तरह भारत ने कोविड-19 की जाँच को तेज़ी से बढ़ाया, उसी तरह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अगली पीढ़ी के टीबी निदान में निवेश कर रहा है ताकि अंतिम छोर तक तेज़ और अधिक सटीक जाँच हो सके।

भारत ने पहले भी समुदाय द्वारा संचालित कार्रवाई की शक्ति देखी है - चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन हो या हमारा पोलियो उन्मूलन अभियान। इसी तरह, टीबी मुक्त भारत अभियान अब लोगों के नेतृत्व वाला एक और आंदोलन बन रहा है। जब नवाचार पहुंच से मिलता है, और जब सरकारें, समुदाय और व्यक्ति एकजुट होते हैं तो असंभव वास्तविकता बन जाता है। भारत सिर्फ़ टीबी से नहीं लड़ रहा है-हम इसे हरा भी रहे हैं।

कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कानूनी प्रणालियों में आधुनिक तकनीक के साथ मानवीय चेतना के संतुलन पर दिया ज़ोर

जालंधर ब्रीज (चंडीगढ़) . समाजसेवी संजय टंडन के नेतृत्व वाली कम्पीटेंट फाउंडेशन ने शनिवार को पंजाब विश्वविद्यालय के लॉ ऑडिटोरियम में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय माननीय जस्टिस मदन मोहन पुंछी की स्मृति में चौथा मेमोरियल लेक्चर आयोजित किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा उत्पन्न उभरती चुनौतियों पर चर्चा के लिए लीगल प्रोफेशनल्स, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के लीडर्स जुटे । इस कार्यक्रम का विषय"टैकलिंग द चैलेंजेज क्रिएटेड बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू द एक्सिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क" था, जिसने इस बात पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया कि कानूनी प्रणालियाँ तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य के अनुकूल कैसे हो सकती हैं। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, कम्पीटेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय टंडन ने जस्टिस मदन मोहन पुंछी की फिलॉसफी के थ्री - एस - समय, सेहत और संबंध पर जोर दिया। टंडन ने कहा, "हम इस सामयिक चर्चा के माध्यम से स्वर्गीय माननीय न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की विरासत को जारी रखने के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हमें यकीन है कि यह कार्यक्रम यह पता लगाने का एक बहुत ज़रूरी अवसर प्रदान करेगा कि न्याय और समानता सुनिश्चित करते हुए एआई की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए कानूनी प्रणाली कैसे विकसित हो सकती है।" लेक्चर को मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख्य अतिथि माननीय जस्टिस अरुण पल्ली, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संबोधित किया, दोनों वक्ताओं ने कानूनी क्षेत्र और व्यापक समाज के लिए एआई के निहितार्थों के बारे में जानकारी प्रदान की।

मेघवाल ने एआई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत नैतिक, नियामक और शासन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे के महत्व पर चर्चा की। प्रसिद्ध शिक्षक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उदाहरण देते हुए उन्होंने वर्तमान युग में लिबर्टी, फ्रटर्निटी एंड इक्वलिटी (स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता) के तार को बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होने कहा की हम उद्योग 4.0 के युग में प्रवेश कर चुके हैं और हम इस चरण से पीछे नहीं जा सकते। आधुनिक उपकरणों के साथ-साथ मानवीय चेतना के साथ विकसित होना समय की मांग है।

जस्टिस अरुण पल्ली के संबोधन में एआई द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए उपलब्ध मौजूदा कानूनी साधनों के साथ-साथ संभावित अंतरालों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने एआई प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास को समायोजित करने के लिए कानूनी प्रणाली को अनुकूलित करने के महत्व कोआउटलाइन किया, जबकि उनके उपयोग में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की। कानूनी विषय की लेखिका श्रुति बेदी ने इस बात पर जोर दिया कि एआई भारत के 4.5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों को सुलझाने में मदद कर सकता है। चीन और एस्टोनिया जैसे देशों से प्रेरणा लेते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे एआई न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है, केस प्रबंधन, कानूनी शोध और अदालती कार्यवाही में दक्षता में सुधार कर सकता है।

अपने वोट ऑफ थैंक्स में, सीनियर एडवोकेट पवन मुटनेजा ने सभी वक्ताओं और उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और कानूनी प्रणाली में एआई की भूमिका पर निरंतर संवाद के महत्व पर जोर दिया।

इस अवसर पर पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु विग, कार्यकारी समिति के सदस्य - आशु मोहन पुंछी, सत्यम टंडन, पवन कुमार डोगरा, महिमा डोगरा टंडन, सुवर्णा मुटनेजा, कम्पीटेंट फाउंडेशन की निदेशक प्रिया टंडन और अन्य भी उपस्थित थे।

वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले में मुख्य पीड़ित बने मुसलमान

वक्फ संपत्तियों का आकार : देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी भूमि वक्फ़ की है। भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली (वामसी) पोर्टल के मुताबिक भारत में वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 37.39 लाख एकड़ से अधिक है। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 32 वक्फ़ बोर्ड विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करते हैं। कुल 8,72,802 वक्फ संपत्तियों के साथ, भारत में वक्फ संपत्तियों का आकार बहुत बड़ा है। इसके अलावा, 4,02,089 'वक्फ बाय यूजर' हैं, लेकिन उनके लिए कोई उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद, केवल 1,088 वक्फ डीड पंजीकृत की गई हैं और 26,676 निजी वक्फ (वक्फ अल औलाद) संपत्तियां हैं।

भारत में वक्फ का इतिहास और वर्तमान संकट : भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन कई विधायी परिवर्तनों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिसका उद्देश्य प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को रोकना है। 1894 में प्रिवी काउंसिल के आदेश के बाद से, मुस्लिम वक्फ अधिनियम संशोधन (1913, 1923, 1930), वक्फ अधिनियम 1954 और इसके बाद हुए संशोधनों सहित विभिन्न कानूनों ने वक्फ प्रशासन को आकार दिया है। वक्फ अधिनियम, 1995 ने विनियामक तंत्र को और मजबूत किया, जिसमें 2013 में एक प्रमुख संशोधन ने इसके दायरे का विस्तार किया।

इतना शानदार इतिहास होने के बावजूद, भारत में वक्फ बोर्ड अनियमितताओं और कुप्रबंधन के आरोपों में घिरे हुए हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए वक्फ संपत्तियों को अक्सर अवैध रूप से बेचा जाता है या निजी संस्थाओं को औने-पौने दामों पर पट्टे पर दे दिया जाता है। बड़े पैमाने पर हुए इस भ्रष्टाचार ने मुस्लिम समुदाय के भीतर बढ़ती अशांति को जन्म दिया है क्योंकि अतिक्रमण, अवैध भूमि लेनदेन और कानूनी विवादों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि, भले ही इस समस्या को व्यापक रूप से पहचाना जाता है, लेकिनअधिकांश समुदाय के सदस्य सामाजिक प्रतिक्रिया और साथियों के दबाव के डर से बोलने से बचते हैं।

बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और कानूनी विवाद : वक्फ संपत्तियों के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण है, जिस कारण कई कानूनी लड़ाइयां हो रही हैं। वामसी पोर्टल के अनुसार, वर्तमान में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के 58,890 मामले हैं। वक्फ संपत्तियों से संबंधित कुल मुकदमेबाजी के मामलों की संख्या 31,999 है, जिनमें से 16,140 मामले विशेष रूप से अतिक्रमण से संबंधित हैं। इनमें से 3,165 मामले

जालंधर ब्रीज

हर्ष रंजन
(वरिष्ठ पत्रकार)

मुस्लिम याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए हैं। मुस्लिम समुदाय के कई लोगों का मानना है कि वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के चलते भ्रष्ट अधिकारियों और निहित स्वार्थी लोगों के लिए इन संपत्तियों का दोहन करना संभव हुआ है, जिससे समुदाय को उसके सही संसाधनों से वंचित किया जा रहा है।

बोलने का डर और आंतरिक संघर्ष : इस मुद्दे ने समुदाय के भीतर आंतरिक कलह को जन्म दिया है क्योंकि लोगों को तेजी से एहसास हो रहा है कि वक्फ संपत्तियों का कुप्रबंधन मुख्य रूप से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि, सामाजिक दबावों के कारण खुलकर आलोचना करना दुर्लभ है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रमुख मुस्लिम हस्तियों, शिक्षाविदों और विचारकों ने वक्फ कानून सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बढ़ती लेकिन अव्यक्त आम सहमति को उजागर किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कई समुदाय के प्रभावी लोग धार्मिक और राजनीतिक समूहों से प्रतिक्रियाओं के डर से इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बोलने में हिचकते हैं।

पूरे भारत में मुकदमेबाजी और शिकायतें : अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के बारे में कई शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अतिक्रमणों का पैमाना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें अक्सर वक्फ बोर्ड की प्रत्यक्ष संलिप्तता होती है। विभिन्न शहरों में कई मामले संकट की सीमा को उजागर करते हैं:

भोपाल में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक वक्फ कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और 125 पंजीकृत कब्रिस्तानों में से 101 रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। हैदराबाद में अकेले 2021 में अतिक्रमणकारियों को 765 नोटिस जारी किए गए, जबकि भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के पास 5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है, फिर भी इसकी 75% जमीन पर अतिक्रमण है। मुंबई में, महाराष्ट्र की 60% से अधिक वक्फ भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, परेल में मूल रूप से 72 एकड़ में फैली लाल शाह बाबा दरगाह, अब वक्फ भूमि पर बने आवासीय टावरों से घिरी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि लखनऊ मेंवक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई 78% भूमि वास्तव में सरकारी स्वामित्व वाली है और 1989 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसने अवैध रूप से गैर-खेती योग्य भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया था। पटना में, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हिंदू बहुल गांव गोविंदपुर, फतुहा में भूमि के स्वामित्व का दावा करते हुए एक नोटिस जारी किया, जिससे सात हिंदू परिवार प्रभावित हुए।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है : वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके माध्यम से मुसलमानों के साथ अन्याय करने का दावा भ्रामक है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य समुदाय के लाभ के लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि सामुदायिक संपत्तियों के आगे दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ बोर्डों को पूरी तरह से बदलना चाहिए। कुछ लोगों का सुझाव है कि वक्फ संपत्तियों को सख्त सरकारी निगरानी के तहत लाया जाना चाहिए, जिसमें निर्णय लेने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले तंत्र हों। वक्फ मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि सामुदायिक कल्याण के लिए बनाई गई संपत्तियां भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं बननी चाहिए।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की मुख्य विशेषताएं : वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वक्फ संपत्तियों से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के रूप में सराहा जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के भीतर प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करना है। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और उन्हें वामसी पोर्टल पर अपलोड करने में विफलता रही है। संशोधन में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी वक्फ संपत्तियों को छह महीने के भीतर ऑनलाइन पंजीकृत किया जाए, ताकि अधिक पारदर्शिता और पहुंच में आसानी सुनिश्चित हो सके।

सरकार का होमवर्क और परामर्श : सरकार ने पिछले आठ वर्षों में मुस्लिम समुदाय के साथ व्यापक परामर्श किया है, जिसमें वक्फ से संबंधित मुद्दों और संभावित सुधारों पर देशव्यापी चर्चाएं शामिल हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, जिसने जनता की प्रतिक्रिया लेने के लिए पूरे भारत में 36 बैठकें कीं।

पंजाब पुलिस को आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस किया जा रहा : मुख्यमंत्री

प्रदेश भर के थानों के लिए 139 नए वाहनों को दिखाई हरी झंडी, पंजाब से नशे के खतरे को खत्म करने की ली शपथ

• **जालंधर ब्रीज.** फिल्लौर (जालंधर)

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार पंजाब पुलिस को बेहतर बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से लैस कर रही है और इसे वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक बना रही है ताकि यह बल कानून व्यवस्था की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो सके। प्रदेश भर के थानों के लिए 139 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के साथ राज्य के सभी 454 थानों के एस.एच.ओज. को नए वाहन मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पिछले रुझानों के विपरीत है, जब नए वाहन जमीनी स्तर के अधिकारियों के बजाय वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि एस.एच.ओज पंजाब पुलिस का असली चेहरा होते हैं क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े होते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के नाते कई विरोधी ताकतें राज्य की शांति भंग करने के लिए नापाक मंसूबे बना रही हैं, लेकिन पंजाब पुलिस ने हमेशा ऐसी कोशिशों को नाकाम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि पुलिस बल को जांच, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्नत जरूरतों के अनुसार अपडेट किया जाए। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि पंजाब पुलिस पूरी पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ लोगों की सेवा करने की शानदार विरासत को कायम रखेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 प्रतिशत नशीले पदार्थ पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए तस्करी करके लाए जाते हैं और बाद में राज्य में उनकी आपूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ड्रोन की आवाजाही रोकने के लिए एंटी-ड्रोन तकनीक शुरू करके बी.एस.एफ. के साथ हाथ मिलाया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के कारण नशे की तस्करी में भारी कमी आई है, क्योंकि बी.एस.एफ. की एक रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में सख्ती के कारण सीमा पार से तस्करी में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही पंजाब पुलिस में हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती करने का फैसला किया है ताकि पुलिस कर्मियों की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन 2100 पदों के लिए हर साल लगभग 2.50 लाख उम्मीदवार आवेदन करते हैं, इसलिए सभी इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा पास करने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र के साथ-साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह उनकी असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने और नशे के खतरे से छुटकारा पाने में मदद कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है ताकि इस बुराई की रीढ़ तोड़ी जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ दिया है और इस घिनौने अपराध में शामिल बड़े माफियाओं को सलाखों के पीछे डाला गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहली बार राज्य सरकार द्वारा अवैध तरीकों से हासिल की गई नशा तस्करों की संपत्ति को ध्वस्त/जब्त किया जा रहा है ताकि कोई और नशा तस्करी में शामिल होने की न सोचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने सत्ता में आने के 36 महीनों में युवाओं को करीब 55,000 नौकरियां दी हैं।

साल 25-26 के लिए कुल आबकारी राजस्व 11,500 करोड़ के आंकड़े को पार करेगा : चीमा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 207 परचून आबकारी समूहों के लिए अलॉटमेंट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की। यह प्रक्रिया जो 5 मार्च, 2025 को शुरू होकर 2 अप्रैल, 2025 को समाप्त हुई, ने 9,017 करोड़ रुपये के अनुमानित लक्ष्य को पार करते हुए 9,878 करोड़ रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस प्राप्त करके निर्धारित रिजर्व कीमत से 9.5 प्रतिशत की बेमिसाल राजस्व बढ़ोतरी हासिल की, जो पंजाब के आबकारी विभाग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यहाँ जारी प्रेस बयान में यह प्रगटावा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आबकारी विभाग ने ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से 207 रिटेल समूहों को सफलतापूर्वक अलॉट किया है और इस पूरी प्रक्रिया को संबंधित धारकों द्वारा भरपूर समर्थन मिला है। वित्त मंत्री ने इस शानदार सफलता का श्रेय आबकारी नीति 2025-26 में शामिल प्रगतिशील और हिस्सेदार-केंद्रित पहुँच को दिया, जिसे एक पारदर्शी और नियमित शराब व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया।

साल 25-26 के लिए कुल आबकारी राजस्व 11,500 करोड़ रुपये से पार करने पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब आबकारी विभाग की लगातार साल-दर-साल सफलता सीधे रणनीतिक आबकारी नीति का परिणाम है, जो राजस्व उम्मीदों को परिभाषित करने के साथ साथ बाजार तय करते हुये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुचारू बनाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब की गतिशील आबकारी नीति सही कीमतों पर उच्च-गुणवत्ता वाली शराब की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है, जिससे उपभोक्ताओं के हितों के साथ राजस्व की बढ़ोतरी को संतुलित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है। वित्त मंत्री ने शराब के गैर-कानूनी व्यापार और तस्करी (अंतर-राज्य और राज्य दोनों) पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की।

पंजाब की प्राचीन शान की बहाली के लिए कर रहे हैं अथक मेहनत : सीएम मान

लुधियाना में वर्ल्ड स्किल कैंपस ऑफ एक्सीलेंस जनता को समर्पित, युवाओं की तकदीर बदलने वाला बताया भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार रोज़ाना टोल दरें बढ़ा रही है, जबकि हमने प्रदेश में 17 टोल प्लाजा बंद किए

• **जालंधर ब्रीज.** लुधियाना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि तीन साल तक पिछली सरकारों की गड़बड़ी को ठीक करने के बाद अब राज्य सरकार पंजाब की प्राचीन शान की बहाली के रास्ते पर है। यहाँ दो प्रमुख संस्थानों - अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर (एमएसडीसी) पर आधारित "वर्ल्ड स्किल कैंपस ऑफ एक्सीलेंस" को जनता को समर्पित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अफसोस जताया कि पिछली सरकारों की पीछे धकेलने वाली नीतियों और दुर्भावनाओं के कारण राज्य विकास में पिछड़ गया था। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब उद्योग संकट में था, नशा माफिया और गैंगस्टर पूर्ववर्ती शासकों के संरक्षण में फल-फूल रहे थे और पंजाब का विकास पटरी से उतर चुका था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता संभालने के पहले दिन से ही उनकी सरकार राज्य के समग्र विकास और जनता की खुशहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता से किए लगभग सभी वादे पूरे कर दिए हैं, और जो वादे नहीं किए गए थे, वे भी पूरे कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार रोज़ाना टोल दरें बढ़ा रही है, जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार ने पंजाब में 17 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसी तरह हर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ तैयार की गई हैं और उन्हें लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से पंजाब के 153 ब्लॉकों में से 117 में भूमिगत जल समाप्त हो चुका है और ये क्षेत्र 'डार्क ज़ोन' में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी भूजल संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किया और पाँच नदियों की इस धरती पर नहरों के अंतिम छोर पर बसे किसानों को कभी भी नहरी पानी उपलब्ध नहीं हुआ। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 'आप' सरकार के सत्ता संभालने के बाद राज्य में 15,947 नहरों की सफाई की गई, जिससे दूरदराज़ के गाँवों तक भी नहरों का पानी पहुँचा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जुलाई 2022 से घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करनी शुरू की है, जिसके बाद 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य सरकार ने पंजाब को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसी निजी कंपनी से पावर प्लांट खरीदा है। उन्होंने कहा कि इस थर्मल प्लांट का नाम तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पूर्ण रूप से सांप्रदायिक सौहार्द्र, शांति और सद्भाव है, जो मुख्य रूप से राज्य के समग्र विकास और खुशहाली के लिए ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के सख्त प्रयासों के कारण पिछले तीन वर्षों में अब तक राज्य में लगभग 97,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील, सनातन टेक्सटाइल और अन्य प्रमुख कंपनियाँ राज्य में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं।

सांसद राघव चड्ढा ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर केंद्र से पूछे तीखे सवाल

भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कसा तंज

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

राज्यसभा में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भारत में अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक की एंट्री और अमेरिका की तरफ से भारतीय सामान पर लगाए गए टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। चड्ढा ने स्टारलिंक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और इसके संभावित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करने की मांग की है। यह चर्चा उस समय हुई जब भारत सरकार स्टारलिंक को देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लाइसेंस देने की तैयारी कर रही है।

राघव चड्ढा ने अपने सवालों को बेहद जोरदार तरीके से संसद में रखते हुए कहा कि भारत ने हमेशा अमेरिका के प्रति अपनी दोस्ती और वफादारी दिखाई है। हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा फाइनेंस एक्ट में संशोधन कर गूगल टैक्स यानी और इक्विलाइजेशन लेवी को हटाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इससे अमेरिकी कंपनियों जैसे मेटा, अमेजन और गूगल को फायदा मिला, लेकिन भारत को लगभग 3000 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ। लेकिन इसके बावजूद, ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 26 फीसदी का टैरिफ लगा दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। चड्ढा ने इसे भारत के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि इससे हमारी जीडीपी पर 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स का असर पड़ सकता है।

राघव चड्ढा ने कहा, "हमने अमेरिका का दिल जीतने के लिए सब कुछ किया। लेकिन बदले में अमेरिका ने 26 फीसदी टैरिफ लगाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका दिया। उन्होंने भारत-अमेरिका के रिश्तों पर तंज कसते हुए कहा, "अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का।" राघव चड्ढा ने सुझाव दिया कि भारत सरकार को एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को दी जाने वाली मंजूरी रोकनी चाहिए और उसका इस्तेमाल अमेरिका से फिर से टैरिफ को लेकर बातचीत में "बर्गेनिंग चिप" के तौर पर करना चाहिए।

कमिश्नरेट पुलिस ने 25 ग्राम हेरोइन के साथ व्यक्ति को किया गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

चल रहे 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' पहल के हिस्से के रूप में, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने एक और गिरफ्तारी की और 25 ग्राम हेरोइन जब्त की है। पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने बताया कि 01 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की एक पुलिस टीम कपूरथला रोड, वरियाणा मोड़ से लेदर कॉम्प्लेक्स, बस्ती बावा खेल के इलाके में मौजूद थी। गश्त के दौरान उन्हें सड़क किनारे एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। तलाशी लेने पर पुलिस टीम ने उसके कब्जे से 25 ग्राम हेरोइन बरामद की। आरोपी की पहचान

विपिन शर्मा पुत्र कुंदन लाल शर्मा निवासी गांव नंबर एनए 174, किशनपुरा थाना रामा मंडी, जालंधर के रूप में हुई। परिणामस्वरूप, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-61-85 के तहत एफआईआर नंबर 72 दिनांक 01.04.2025 को पुलिस स्टेशन बस्ती बावा खेल, जालंधर में दर्ज की गई।

सैनिक इंस्टीट्यूट के बीएससी (आईटी) के तीसरे समैस्टर में नेहा प्रथम

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

नेहा, अर्पित शर्मा, अनमोलजीत कौर

पंजाब सरकार ने ज़िला रक्षा सेवाएं भलाई दफ्तर में चलाए जा रहे सरकारी कालेज सैनिक इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टैकनॉलॉजी का बैचलर आफ साईंस इन आई.टी.के तीसरे समैस्टर और पी.जी.डी.सी.ए. के पहले समेस्टर का नतीजा शानदार रहा है।

डायरैक्टर-कम-ज़िला रक्षा सेवाएं भलाई अधिकारी जालंधर कमांडर बलजिन्दर सिंह विर्क (रिटा.) ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बी.एस.सी. (आई.टी.) के तीसरे समेस्टर में नेहा ने 8.17 एसजीपीए लेकर पहला और अर्पित शर्मा ने 7.35 एसजीपीए लेकर दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह पीजीडीसीए के पहले समैस्टर में अनमोलजीत कौर ने 7.38 एस.जी.पी.ए. ले कर पहला स्थान हासिल किया है। विद्यार्थियों को शानदार नतीजे के लिए बधाई देते ज़िला रक्षा सेवाएं भलाई अधिकारी ने भविष्य में ओर सख़्त मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया।

राज्य में प्रफुल्लित हो रही खेल संस्कृति

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पंजाब सरकार द्वारा युवाओं को खेल मैदानों की ओर लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के चलते जिला जालंधर में 3.18 करोड़ की लागत से 98 मॉडल खेल मैदान बनने जा रहे है। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि मगनरेगा के तहत अभिसरण योजना के तहत जिले के विभिन्न ब्लाको में 3 करोड़ 18 लाख 86 हजार रुपये की लागत से 98 मॉडल खेल मैदान बनाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से ब्लॉक लोहियां में 23, आदमपुर में 58 और नकोदर में 17 मॉडल खेल मैदान बनाए जाएंगे, जिन पर मनरेगा से 1 करोड़ 74 लाख रुपये और अन्य

फंड से 1 करोड़ 44 लाख 86 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जिले में 98 मॉडल खेल के मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इसके अलावा जिले के विभिन्न ब्लॉकों में 2.40 करोड़ रुपये की लागत से 107 पार्कों का भी निर्माण करवाया जाना है। उन्होंने कहा कि इन पार्कों के बनने से लोगों को सैर करने की सुविधा होगी।

भाजपा धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर कर रही है : प्रताप बाजवा

चंडीगढ़ (जालंध ब्रीज). पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक अधिकारों पर लगातार हमले के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की, जिसका उदाहरण विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 है। बाजवा ने आगाह किया कि यह केवल शुरुआत है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) और इसके संस्थान भाजपा के अतिक्रमण का अगला लक्ष्य हो सकते हैं, इसके बाद ईसाई संस्थानों की स्वायत्तता को कमजोर किया जाएगा। उन्होंने

अनुच्छेद 25 के तहत मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों को खतरे में डालने वाले प्रावधानों पर गहरी चिंता व्यक्त की।

केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड जैसे प्रमुख वक्फ संस्थानों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना, साथ ही एक गैर-मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, धार्मिक स्वायत्तता में अभूतपूर्व घुसपैठ का संकेत देती है। उन्होंने टिप्पणी की, 'मोदी सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ती है, लेकिन यह समुदाय के प्रतिनिधित्व और वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण को खत्म करने का एक स्पष्ट प्रयास है।'

विराट कोहली को अंगुली में लगी चोट, हेड कोच ने कहा- चिंता की बात नहीं

स्पोर्ट्स डेस्क. गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली आरसीबी की टीम की ये आईपीएल 2025 में पहली हार है। टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। बेंगलुरु में खेले गए पहले मुकाबले के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को अंगुली में चोट लगी, जिसे देकर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद फैंस टेंशन में आ गए। हालांकि, टीम के हेड कोच एंडी फ्लावर ने कहा है कि चिंता की बात नहीं है।

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में फील्डिंग करते समय विराट कोहली को अंगुली में चोट लगी। लेकिन फ्लॉवर ने कहा कि स्टार बल्लेबाज की हालत को लेकर कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। फ्लावर ने मैच के बाद कहा कि विराट कोहली ठीक लग रहे हैं, वह ठीक हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आरसीबी को ये मैच आठ विकेट से गंवाना पड़ा जो तीन मैचों में सत्र की उनकी पहली हार थी। गुजरात की पारी के दौरान विराट कोहली ने डीप में बाउंड्री बचाने की कोशिश की लेकिन इस दौरान उनकी अंगुली में चोट लगी। फीजियो ने उनका ट्रीटमेंट किया, इस दौरान वह दर्द में दिखे।

आरसीबी के मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने कहा कि पहले सात ओवरों में चार विकेट खोने से उनकी टीम के लिए परिस्थितियों मुश्किल हो गई थी। फ्लावर ने संवाददाताओं से कहा कि, हमने पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी की लेकिन इस बीच हमने कुछ अहम विकेट गंवाए। इससे मैच का पासा पलट गया। अगर आप पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो इससे आपके लिए परिस्थितियों मुश्किल हो जाती हैं।

फोटो-आईपीएल

कंग ने लोकसभा में बंदी सिंह का मुद्दा उठाया

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली/चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से बंदी सिंहों (सिख कैदियों) की रिहाई के संबंध में 2019 में किए गए अपने वादे को पूरा करने की अपील की। कंग ने सदन को याद दिलाया कि 2019 में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने इन कैदियों की रिहाई की बात की थी जो पहले से ही 25-30 वर्षों से जेलों में बंद हैं और अपनी पूरी सजा काट चुके हैं। उस वक्त बाकायदा अधिसूचना भी जारी की गई थी, लेकिन छह साल बाद भी ये कैदी आज जेल में बंद हैं। मुद्दे के मानवीय पहलू पर प्रकाश डालते हुए कंग ने इस बात पर जोर दिया कि इन व्यक्तियों ने पहले ही अपनी कानूनी सजा पूरी कर ली है और उन्हें अब सलाखों के पीछे नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका लंबे समय तक कारावास मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है और न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। उन्होंने सरकार से इन कैदियों की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों पर विचार करने और उनकी रिहाई के प्रति दयालु दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।

मीत हेयर ने आढ़तियों के कमीशन और पंजाब के लिए स्पैशलें बढ़ाने का मुद्दा उठाया

संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने संसद के शून्य काल के दौरान फसल की खरीद से जुड़े दो अहम मुद्दे उठाते हुए आढ़तियों को गेहूं और धान पर मिलने वाले कमीशन को पहले की तरह एमएसपी का ढाई प्रतिशत निर्धारित करने और गोदामों से धान की ढुलाई को तेज करने के लिए पंजाब के लिए स्पैशलें बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि फसल की खरीद को सुचारू रूप से मुकम्मल करने के लिए इन मसलों का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। मीत हेयर ने कहा कि 2019-20 तक गेहूं और धान पर आढ़तियों का कमीशन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का ढाई प्रतिशत निर्धारित था, जिसे केंद्र सरकार ने

बदलकर 46 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। तब से यह दर वैसी ही चल रही है, जबकि महंगाई बढ़ने से कमीशन जस का तस रहा, जिस कारण हाल के समय में आढ़तियों द्वारा हड़ताल की गई, जिसका सीधा असर पंजाब में फसल की खरीद पर पड़ा। मीत हेयर ने उनका कमीशन फिर से एमएसपी का ढाई प्रतिशत निर्धारित करने की मांग की।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, Near Subhanpur Bus Stand,Hamira, Kapurthala-144802(Punjab) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.